(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् ने मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली तथा अन्य राज्यों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के लिए इसकी गतिविधियां मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस साम्प्रदायिक संगठन को अवैध घोषित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद में दो राज्यों में साम्प्रदायिक स्थिति का पुनर्विलोकन करते समय अन्य बातों के साथ साथ सामान्यत. मुस्लिम लीग की गतिविधियों का उल्लेख किया गया था ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) सदन को मालूम है कि उन संस्थाओं के विरुद्ध जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक मिलाप बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता के हित के प्रतिकूल है, दण्डा-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । इस अधिनियम के प्रावधान उचित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाये गये है । इस प्रश्न पर कि क्या अधिनियम के प्रावधान किसी संस्था के बारे में लागू होने चाहिये, ऐसी संस्थाओं के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार द्वारा विचार किया जाता

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 7425 DT. 18-4-73 REGARDING PAYMENT OF CESS BY SALT MANUFACTURERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): In answer to the Unstarred Question No. 7425 in the Lok Sabha on the 18th April, 1973, it has been stated as under:

"(a) Statement No. I indicating the cess collections during the last three years, State-wise and year-wise, is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No LT-5360/73].

(b) Statement No. II indicating the expenditure on development and other works during the last three years, State-wise and year-wise, is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-5360/73] "

The Statement Nos I and II referred to in the reply quoted above are attached The figures furnished therein were based on the information furnished by the Salt Commissioner who had obtained the same on phone from his Regional Officers all over the country Later on it came to the notice of the Salt Commissioner that some of the figures furnished by his Regional Officers on phone were not passed on correctly It has since been reported by the Salt Commissioner that the correct figures are as indicated in the Statements III and IV is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5360-73].

Reasons for Delay:

The inaccuracy of the figures given in the answer could not be corrected in time, as this came to the knowledge of this Ministry much after the question was answered.